

क्या बंगाल में भाजपा का “ट्रंप कार्ड” साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने “भद्रलोक” (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक “ट्रम्प कार्ड” के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरबी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता

बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन ‘भद्रलोक’ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितां के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केन्द्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितां के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आयवित्तवर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथेनॉल युक्त पेट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
- लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।

की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एग्रो इंडस्ट्रीज भी ऐथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।

वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी

गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कई उपभोक्ताओं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ई20 पयूल कोरोसिव (संश्लारक) प्रकृति का है और अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों के इंजनों की उम्र कम कर सकता है। कुछ रिपोर्टों में माइलेज में 3 से 8 प्रतिशत तक की गिरावट और पयूल सिस्टम तथा रबर गैस्केट को नुकसान की आशंका जताई गई है।

नितिन गडकरी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें पेड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आईपीएस पंकज चौधरी के बकाया प्रमोशनों पर प्रोविज़नल तौर पर विचार करें’

जयपुर, 22 दिसंबर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चल रहे प्रमोशन पर प्रोविजनल तौर पर विचार

- केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

करे। अधिकरण ने यह आदेश पंकज चौधरी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले से जुड़े अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि प्रार्थी के खिलाफ चल रहे केसों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के प्रमोशन शामिल हैं। इसके साथ ही साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन भी रुका हुआ है। राज्य सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारत हिंदू राष्ट्र है’

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि इसके लिए किसी संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सच है।

आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और तब तक रहेगा जब तक देश में भारतीय संस्कृति को महत्व दिया जाता रहेगा।

भागवत ने कोलकाता में आरएसएस के ‘100 व्याख्यान माला’

- संघ प्रमुख भागवत ने यह दावा करते हुए कहा, संविधान में हिंदू राष्ट्र शब्द जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो भी ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है यह सत्य है।

कार्यक्रम में कहा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। हमें नहीं पता यह कब से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी हमें संविधान को मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, वह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीएमसी चुनाव में एक हुई मुम्बई की “फर्स्ट फैमिली”

20 सालों में यह पहली बार है जब उद्धव और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। मुंबई की राजनीति में ‘पहला परिवार’ माने जाने वाले ठाकरे परिवार ने सोमवार सुबह एक बड़े चुनावी पुनर्मिलन की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक, अगले महीने होने वाले बृह-मुंबई महानगरपालिका चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर इस परिवार में आधिकार सहमति बन गई है।

पिछले 20 वर्षों में यह पहला अवसर होगा, जब ठाकरे परिवार के दो सबसे बड़े नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

इस बीच, कांग्रेस इस व्यवस्था का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थिति महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के भीतर तनाव को दर्शाती है, खासकर ठाकरे भाइयों के एकजुट होने के बाद। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में एमवीए को झटका लगाने के बाद भी, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक वापसी की उम्मीद है।

बड़े संकटों के दौर में, दलितों, मुसलमानों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर, देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा जताया है।

- बीएमसी की 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना 157 और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।
- इस नई व्यवस्था में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सहयोगी दलों, कांग्रेस व एनसीपी (शरद पवार) को कोई जगह नहीं मिली है इससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अप्रत्याशित नहीं रहे और भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस ने भी इन चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक हल्की सी चुनौती पेश की।

इस सफलता का श्रेय कांग्रेस नेता विजय वडेड़ीवार, कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रतिभा धनोरकर और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाले को जाता है।

कांग्रेस द्वारा जीते गये कुल 34 नगर परिषद अध्यक्ष पदों में से आठ सीटें चंद्रपुर जिले की और तीन सीटें बुलढाणा जिले की थीं।

विश्वजोत कदम अपने गढ़ को बचाने में सफल रहे, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधायक

अमित देशमुख अपनी पकड़ बनाए रखने में असफल रहे।

शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में, भाजपा ने कुल 288 में से 120 नगर परिषद अध्यक्ष पद जीते, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 56 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 36 पद मिले।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सूत्रों ने बताया कि शिव सेना बीएमसी की 227 सीटों में से 157 पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शेष 70 सीटों पर उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने उम्मीदवार उतारेंगी।

इस व्यवस्था के बाद, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना-नेतृत्व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथेनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्त तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कटीती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के पयूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है वहीं स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी

ऐथनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथेनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथेनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथेनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील को

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “बैड डील” करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट – एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “खराब समझौता” करार देते हुए कहा कि यह “बहुत अधिक देने” तथा “बहुत कम” प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूजीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंगटन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में “सबस्टैस” का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो “न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी” के नेता और सरकार में गठबंधन साझीदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी “खेद सहित” इस समझौते के खिलाफ

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूजीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, “हम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।” उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

की रक्षा करने में विफल रहा है।

उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक खराब समझौता है। यह देता बहुत ज्यादा है, खासकर आप्रवासन के मामले में, और न्यूजीलैंडवासियों के लिए बहुत कम प्राप्ति करता है, जिसमें डेरी उत्पाद क्षेत्र भी शामिल है।

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एसएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी।

। लोग पीड़ी देर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी।

यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 बनाया। 2009 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 40 प्रतिशत से अधिक न हो एवं 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 10 प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत से भी कम भुगतान पडता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं। कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंगे सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंगे गाड़ी खरीद ली थी। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था। सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2009 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 15 दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित कराया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजाम में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरों में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

2005 से 2025 तक लगभग 20 वर्ष तक नरेगा अकुशल श्रमिकों के लिए

;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 15.5 करोड़ जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 200 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 100 दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 45 दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 125 दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2015 में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 10 वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं। वह इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे? अब तक राज्यों पर 10 प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पडता था जो बढ़कर अचानक 40 प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि श्रष्टों को तोड़ मरोड़ करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख-राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू-राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों को केंद्रीकरण कर दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है। इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 700 किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली पर न्याय का संदेश : संरक्षण जिम्मेदारी का संतुलन



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थाओं द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस 500 मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

814वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूँ, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरूद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री को स्वागत कर दस्तारबंदी कर उर्स की मुबारक दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री

2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलैक्टर लोक बंधु,

जोधपुर एम्स में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एम्स में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं। इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एम्स में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिवर दिल्ली भेजा गया है।

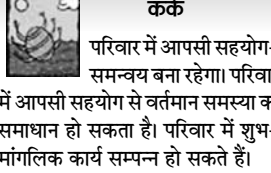
एम्स के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिड़ा के रहने वाले भोमाराम (5) पुत्र भैराराम को बार-बार दौरें पड़ने की समस्या पर 15 दिसंबर को एम्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

■ **पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए**

स्टेट्स एस्प्लिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग



चलते कार्यो में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

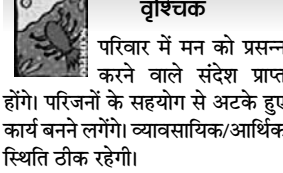


नवीन कार्यो के संबंध में सरकारत्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यो में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यो में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।



चर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

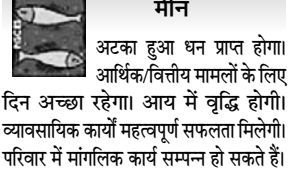
चर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

लगाई गई। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि इस अंगदान से दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। ट्रांसप्लांट के नोडल अधिकारी दो शिवचरण ने बताया कि ऑर्गन डोनेट करने के बाद पांच से छह घंटे में लगाना जरूरी होता है, इसलिए लिवर को फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया।

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उसव जैसा माहौल रहेगा।



मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।



चर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अगर्गत कार्यो में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यो महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

पारदर्शी ढांचा लागू हो रहा है, तब उसी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा करना जनभावनाओं को भ्रमित करने का प्रयास है।

सरकार की नीति केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। जून 2025 में शुरू की गई अरावली 'ठीन वॉल' परियोजना इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। चार राज्यों के 29 जिलों में पांच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाकर 2030 तक करोड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल बताती है कि सरकार अरावली को केवल बचाने नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करना चाहती है।

अरावली प्रकरण में वास्तविक संघर्ष पर्यावरण और विकास के बीच नहीं, बल्कि तथ्य और भ्रम के बीच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और केंद्र सरकार की नीति यह स्पष्ट करती है कि अरावली के संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वर्षों से चली आ रही अस्पष्टताओं को समाप्त कर एक वैज्ञानिक, न्यायिक और जवाबदेह ढांचा स्थापित किया गया है।

आज आवश्यकता है कि अरावली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति तथ्यों के साथ खड़ी हो, क्योंकि अरावली का प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी,
अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा की

जैसलमेर, (नि.सं.)। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) मदनलाल भाटी ने सोमवार को जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित पंचायत समिति जैसलमेर के सभागार में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं प्रतिभागियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद एवं खुली परिचर्चा की।

ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इस जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य आयोग द्वारा आमजन से सीधे संवाद स्थापित कर ओबीसी वर्ग से जुड़े क्षेत्रवार मुद्दों, विकास संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों एवं कल्याण से जुड़ी समस्याओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों को संकलित करना है, ताकि इनके आधार पर पंचायती राज एवं नगरीय निकायों

में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक समठा एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा सके। उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालन में आयोग को राज्य के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति, उसकी तीव्रता एवं उसके प्रभावों का समसामयिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन करना है। इस अध्ययन के आधार पर आयोग को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में ओबीसी आरक्षण के संबंध में समयबद्ध अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी हैं।

भाटी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। इसके लिए पंचायती राज एवं शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को

आरक्षण देने का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक फार्मूला तय कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर प्रदेश में आरक्षण लागू किया जाएगा।

खुली परिचर्चा के दौरान पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, पूर्व नगर विकास न्यास अध्यक्ष उमेशसिंह तंवर, पूर्व नगरपरिषद सभापति अशोक तंवर, पूर्व उप सभापति खींवसिंह, कर्नल (से.नि.) अचलाराम पंवार सहित अन्य वक्ताओं ने आयोग अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार रखे।

इस अवसर पर वक्ताओं ने मूल ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण एवं तमिलनाडु मॉडल के अनुरूप कार्यक्रम में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर जितेंद्रसिंह सादू एवं आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर लजपालसिंह सोढ़ा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर जितेंद्रसिंह सादू एवं आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर लजपालसिंह सोढ़ा भी उपस्थित रहे।

जनसंवाद के माध्यम से प्राप्त सुझावों को आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे प्रदेश में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल सके।

योजनाओं का प्रचार

जालोर, (का.सं.)। राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से जिले के पाँचों विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। सोमवार को विकास रथ आहोर विधानसभा की मेड़ा उपरला, चांदना, सियाणा, रायपुरिया व सिवणा,, जालोर विधानसभा की पोषाणा, उनडी, देताकलां व कोमता, भीनमाल विधानसभा की नरसाणा, धुम्बडिया, लाखनी, भालनी व बाली, सांचौर की गोमी, जानवी में पहुंचे।

अरावली के लिए रैली निकाली

रेवदर, (निसं)। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय की ओर से परिभाषित करने के बाद प्रदेश भर में पर्यावरण प्रेमी अरावली बचाने को एकजुट होकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोही जिले की तहसील रेवदर के सभी पर्यावरण प्रेमीयो ने मिलकर राजनीति से परे अरावली बचाने को लेकर अरावली बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर कस्बे के सरसी माता मंदिर परिसर में अरावली बचाओ के आह्वान

पर लोग एकत्रित होकर उपखण्ड मुख्यालय के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए उपखण्ड कार्यालय पहुंचे। उपखण्ड अधिकारी राजन लोहिया को ज्ञापन सौंप कर अरावली बचाने की मांग का ज्ञापन उच्च स्तर पर भिजवाने का निवेदन किया। सर्वोच्च न्यायालय में अरावली की जो परिभाषा दी गई है वह भूगोल के विरुद्ध है और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। अरावली बचाओ आंदोलन समिति तहसील रेवदर ने अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे लगाकर इस व्याख्या के विरुद्ध अपनी

आपत्ति दर्ज करवाई।

किसान सम्मेलन का होगा सीधा प्रसारण

जालोर,(नि.सं.)। 23 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे जिला संदर्भ केन्द्र में किसान सम्मेलन किया जायेगा। जिला स्तरीय सम्मेलन में नागौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य किसान सम्मेलन-उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा।

सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह की तैयारी पर चर्चा की

पाली, (नि.सं.)। पाली सांसद और एक राष्ट्र, एक चुनाव जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सोमवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इस बैठक में 25 दिसंबर, बांगड़ स्टेडियम में होने वाले सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में समापन समारोह का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीच सुचारु समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आभासी रूप से संबोधित करेंगे। सांसद चौधरी ने कहा कि 25

दिसंबर को होने वाला समापन समारोह बांगड़ स्टेडियम में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों सहित विधायक, जिला प्रशासन, वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल होंगे। यह गत 3 नवंबर को शुरू हुए सांसद खेल महोत्सव का सफल समापन होगा।

सांसद चौधरी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आठों विधानसभाओं को अंतिम निर्देशों के अनुरूप, ज़िला-स्तर और संसदीय क्षेत्र-स्तर की भागीदारी सहित विविध कार्यान्वयन मॉडलों के लिए पूरी तरह

तैयार करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के आभासी संबोधन को ध्यान में रखते हुए पुख्ता कनेक्टिविटी और समुचित बुनियादी सुविधाओं समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक में सांसद खेल महोत्सव के दीर्घकालिक विज्ञान पर प्रकाश डालते हुए सांसद चौधरी ने कहा कि यह पहल सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पूरे देश में खेल से संबंधित टिकाऊ इकोसिस्टम तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने इस बात की ओर भी इंगित किया कि समापन समारोह का

आयोजन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के साथ हो रहा है, जो शासन, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र-निर्माण के विषयों को जोड़ने का अवसर देता है। उन्होंने आयोजन को लोगों तक पहुँच और प्रसार-प्रचार बढ़ाने के लिए संपूर्ण पाली एवं जोधपुर जिले में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप ही इसे समन्वित एवं सफल मंचन करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। कलेक्टर एलपन मंत्री एवं आयोजन से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यालय नगर परिषद जालोर (राज.) (अस्पताल चौराहा जोधपुर रोड जालोर-343001)					
भूमि		आपत्ति आमंत्रण सूचना		दिनांक-20.12.2025	
Tel. 02973-222270		Email: mbjalore24@yahoo.in		76	
क्रमांक-नपजा/भूमि नियमन/2025/6448		आपत्ति आमंत्रण सूचना		आपत्ति आमंत्रण सूचना	
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद क्षेत्र जालोर के 69ए पट्टे के बदल पट्टा व खांवा भूमि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाकर पट्टे की मांग की गई है। इस संबंध में किसी व्यक्ति आदि को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य आपत्ति सूचना पत्र के प्रकाशन होने के 07 दिवस के भीतर-भीतर नगर परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं आवेदकों के नाम पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।		आपत्ति आमंत्रण सूचना		आपत्ति आमंत्रण सूचना	
क्र. सं.	प्रकरण	आवेदक का नाम/पता व भूखण्ड का पता	आह्वस-पट्टीस चतुर्दश	भूखण्ड का क्षेत्र. (वर्गज)	प्रयोजन का प्रकार
1	128/2025-26	श्री हेमराज जैन पुत्र चुनौलाल जैन कल्याण नगर जालोर	उत्तर-प्लोट नं. 49 दक्षिण- प्लोट नं. 90 पूर्व- प्लोट नं. 84 पश्चिम- रास्ता	355.55	आवासीय
2	129/2025-26	श्रीमती सतोष देवी पति चुनौलाल अखाड़ा गली तिलक द्वार के अन्दर जालोर	उत्तर-प्लोट नं. चंदन सिंह दक्षिण- प्लोट नं. अखाड़ा भूमि पूर्व- प्लोट नं. चौक पश्चिम- अन्य भूमि	133.33	आवासीय
3	130/2025-26	श्रीमती अनीता देवी पति ओटाराम महादेव जी गली जगन्नाथ मंदिर राजेन्द्र नगर जालोर	उत्तर-प्लोट नं. महेन्द्र/डायाराम दक्षिण- प्लोट नं. ताराराम/छोहाराम पूर्व- चम्पालाल/तेजाराम पश्चिम- आम रास्ता	95.00	आवासीय
4	131/2025-26	प्रधान डाकघाल जालोर सिवाजी नगर जालोर जरिये फूलाराम सोलंकी पुत्र केराराम सोलंकी	उत्तर-प्लोट नं. रास्ता 50 फिट दक्षिण- प्लोट नं. रास्ता 50 फिट पूर्व- प्लोट नं. रास्ता 50 फिट पश्चिम- रास्ता 50 फिट	3966.00	आवासीय
5	132/2025-26	प्रधान डाकघाल जालोर सिवाजी नगर जालोर जरिये फूलाराम सोलंकी पुत्र केराराम सोलंकी	उत्तर-प्लोट नं. रास्ता 50 फिट दक्षिण- रास्ता 50 फिट पूर्व- रास्ता 50 फिट पश्चिम- रास्ता 50 फिट	2000.00	आवासीय
6	133/2025-26	श्रीमती चुकी देवी पति नारारणलाल एफसीआई गोदाम के पीछे, जालोर	उत्तर-प्लोट नं. मुक्ताराम का मकान दक्षिण- रास्ता 25 फिट पूर्व- होसाराम भील का मकान पश्चिम- रास्ता 25 फिट	1500.00	आवासीय
आयुक्त, नगर परिषद जालोर					



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



2 साल
नव उत्थान - नई पहचान



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
₹2,000 + करोड़ की स्वीकृति

राज्य परियोजनाओं से कृषकों
को ₹1,200 करोड़ का हस्तांतरण

मुख्य अतिथि
श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अध्यक्षता
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

नागौर जिले में ₹351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

राशि हस्तांतरण

कृषि एवं उद्यानिकी योजनाएं
31,600 कृषकों को ₹200 करोड़

कृषि आदान-अनुदान
5 लाख कृषकों को ₹700 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
18,500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना
4.50 लाख पशुपालकों को ₹200 करोड़

23 दिसम्बर, 2025 | अपराह्न 12:00 बजे | डांगावास, मेड़ता सिटी (नागौर)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

बजरी माफिया से सांठगांठ पर 1 1

पुलिस निरीक्षकों पर गाज गिरी

पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने प्रदेशभर में किया डिकॉय ऑपरेशन

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और गंभीर लापरवाही रखने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा डिकॉय ऑपरेशन करने के बाद यह कार्रवाई हुई।

प्रदेशभर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में पांच पुलिस निरीक्षकों को तत्काल निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य को लाइन हाजिर किया

- पांच पुलिस निरीक्षक निलंबित, अन्य 6 को लाइन हाजिर किया

गया है।

एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने

आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था,बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी।

जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरीनी, अजमेर के पीसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाडी व नात्ता, दोसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगारार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थाना अधिकारियों को

लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं : पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले नवंबर माह में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो एफआईआर दर्ज न करने, परिवारियों से दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम की शिकायतों पर हिलाई, एसपी ऑफिस में प्राप्त परिवारों में परिवाद अनुभाग की कार्यप्रणाली, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली एवं कार्यशैली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन किया गया था।

बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह की शहादत के किस्से आमजन तक पहुंचायेगी भाजपा : टीटी



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की।

के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठियां, स्कूलों एवं कॉलेजों में

विचार संगोष्ठियां तथा भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी। इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहित्यजादों की शहाबाद व किशनगंज प्रदर्शनी भी लगाएंगे, जिससे उनकी गौरवशाली गाथा जन-जन तक पहुंच सके।

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 5 साल पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। स्वतंत्रता के दशकों बाद तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। जिसके तहत सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आक्विफरी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर

इसमें प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य शामिल किया गया। इसी लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किमी. से अधिक सड़कों का निर्माण किया और 15983 बसावटों/गांवों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा। यह केवल सड़कों का विस्तार नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और नये अवसरों को पहुंचाने की पहल रही है। चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण प्रदेश में पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का

- प्रदेश में 75 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें तथा 68 गुल बनाकर 15983 बसावटों को जोड़ा गया
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेड़ता में 2089 करोड़ रुपये लागत की 1216 पीएमजीएसवाई सड़कों की सौगात देंगे

आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि, कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मेड़ता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण में प्रदेश की 1216 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने व एक गुल की

सौगात देंगे। जिनकी अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ होगी।

गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश

में लगभग 12086 करोड़ रुपये की लागत से 49730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 14043 किमी. सड़कों के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चर्यानित “शू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क” को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ नयी सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों के नेटवर्क को और अधिक

मजबूत करना भी आवश्यक है। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण-सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। अब तक प्रदेश में 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किमी. की 903 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 पुलों

का निर्माण किया, शेष कार्य प्रगतिरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम-जनमन योजना का शुभारम्भ किया था, जिसके तहत बारां की शहाबाद व किशनगंज ब्लॉक की सहरीया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 11 करोड़ की लागत से 22 किमी. सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।

एम.एन.आई.टी. में प्रस्तावित ट्रेड फेयर पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीपीजे सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिवाचक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में अभिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और

- बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित 3 दिवसीय इस ट्रेड फेयर में सोलर क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों निर्माता और सेवा कंपनियां भाग लेंगी
- याचिका में कहा गया कि, “संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।”

शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते

है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के प्रावधान हैं। ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुड़े लोगों को यहां प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर के आयोजन को रोका जाए। याचिका में पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भारत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है।

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए है, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का ख़र्चन मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है। आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉपन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा। सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर मैकिंग चार्ज पर फ्लैट 20



फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वेलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टायल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

“जयपुर ज्वैलरी शो” कला-विरासत और परंपरा का उत्सव : प्रेमचंद बैरवा जे.ई.सी.सी. में जे.जे.एस. संपन्न हुआ, बीते 4 दिनों में करीब 4 6 हजार विजिटर्स ने की शिरकत



जयपुर ज्वैलरी शो के समापन समारोह में सोमवार को उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वैलरी प्रस्तुति के अवार्ड देकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

जयपुर (कासं)। जयपुर आभूषण की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है और जयपुर ज्वैलरी शो इस शहर की समृद्ध विरासत, परंपरा और कला का उत्सव है। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर ज्वैलरी शो 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार प्रातिशील नीतियों और ईए ऑफ दूइंग बिजनेस के जरिए इस उद्योग को सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेजेएस वार्ड्स चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने कहा कि अपने शुरुआती

- 18 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा आगामी संस्करण

वर्षों में मात्र 67 बूथों से शुरू होकर आज 1227 बूथों तक पहुंचना इस शो की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। आज यह एजोबिशन देश की सबसे बड़ा बी2बी और बी2सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है।

जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने बेस्ट बूथ अवॉर्ड्स की घोषणा की। उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वेलरी प्रस्तुति के लिए 18 वर्ग मीटर से ऊपर बेस्ट बूथ ज्वेलरी श्रेणी में विजेताओं में पहला स्थान बिरछीचंद घनश्याम दास ने जीता। दूसरे स्थान पर

मोहनलाल नारायणदास ज्वैलर्स रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी (आईआईजीसी) को बेस्ट इंस्टीट्यूट अवॉर्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने शो के अगले संस्करण की तारीखों की भी घोषणा की, जो 18 से 21 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होगा। जैन ने बताया कि इस वर्ष शो में 46 हजार से ज्यादा विजिटर्स आए, जिनमें से 15 हजार बाहर के शहरों से थे।

जेजेएस के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता अजय काला ने समापन समारोह का संचालन किया। उन्होंने कहा कि इस बार जेजेएस व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधन की दृष्टि से भी व्यापक और उपयोगी शो रहा। उन्होंने शो की सफलता के लिए सभी प्रदर्शकों, चित्रेताओं और आगंतुकों का आभार जताया।

सार-समाचार फैशन और ज्योतिष का अद्भुत संगम



जयपुर । अलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव (एआईएसी) सीजन-2 के अंतर्गत आयोजित लीटरिंग जोडियक फैशन शो ने फैशन और ज्योतिष के अद्भुत संगम को भव्य मंच पर प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अनूठे आयोजन में राशियों की ऊर्जा, रंगों और भावनाओं को फैशन के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. मेधा शर्मा ने बताया कि यह भव्य आयोजन ऑलमाइटी इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल वास्तु अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। शो की परिकल्पना और निर्देशन, मिससे इंडिया इंटरनेशनल दीपिा सैनी ने संभाली। इस विशेष फैशन शो में प्रीति सचदेवा, युविका जैन, मीनाक्षी सोलंकी, अमृता टांगीयाना, ममता जायसवाल, अंशु वाघवा और इंद्रजीत दास ने विभिन्न राशियों पर आधारित डिजाइनों को आत्मविश्वास, गरिमा और सौंदर्य के साथ रैप पर प्रस्तुत किया। प्रत्येक प्रस्तुति में संबंधित राशि के रंग, व्यक्तित्व और कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिला। शो की विशेष आकर्षण रही शोर्ट्सटॉपर आरजे देवांगना, जिन्होंने रैप पर अपनी दमदार उपस्थिति से समा बांध दिया। मंच पर मेष की ऊर्जा, सिंह की शाही भव्यता, तुला का संतुलन और कर्क की कोमलता फैशन से सजीव हुई।

ब्राइट फ्यूचर स्कूल में क्रिसमस पर्व मनाया

जयपुर । जनता कॉलोनी स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल ने बड़े उत्साह



और खुशी के साथ “क्रिसमस” पर्व मनाया। लाल और सफेद रंग की पोशाक पहनकर छोटे-छोटे बच्चों ने क्रिसमस कैरौल की धुन पर गाकर और नाचकर बुशियां फैलाई। अनर्गल छोटे सांता क्लॉज ने माहौल को जादुई बना दिया और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार और मनमोहक पल बनाए। यह उत्सव हंसी, संगीत और एकजुटता की भावना से भरा था। उत्साह को बढ़ाते हुए, डायरेक्टर तेजेंद्र शर्मा और गौरव तेज शर्मा ने बच्चों को बेस्ट डॉसर, बेस्ट ड्रेस्ड, बेस्ट पोस्टर मेकर और अन्य कैटेगरी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

वीकेंड के बाद भी सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में रौनक बरकरार



जयपुर । सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 में वीकेंड के बाद भी उत्साह और चहल-पहल कम नहीं हुई। सोमवार को मेले के पाँचवें दिन सामान्य कार्यदिवस होने के बावजूद मेला परिसर में भीड़ देखने को मिली। शिल्प, हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने मेले को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया।

परिवारों के साथ आए दर्शकों ने विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की सरहना की और स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल के स्कूली बच्चों ने भी मेले का भ्रमण किया।

बच्चों ने महिला उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका और स्वदेशी उत्पादों की नजदीक से समझा, जो उनके लिए आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव रहा। महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मेले के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा कमला पोद्दार ग्रुप के सहयोग से एक विशेष उत्पाद संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसएचजी महिलाओं को डिजाइन नवाचार, गुणवत्ता सुधार और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद विकसित करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया।

गजसिंह के जन्मदिन पर आठ प्रतिभाओं का सम्मान किया

जोधपुर, (कासं)। मारवाड़ में सांस्कृतिक परम्पराओं, छत्तीस कौम से जुड़ाव व अपनायत रखने वाले जोधपुर के पूर्व नरेश गजसिंह का 78 वां जन्मदिन तिथि अनुसार सोमवार ,22 दिसंबर को उम्मेद भवन पैलेस के राठौड़ दरबार हॉल में पूर्ण राजसी परम्परा, गरिमा के साथ अनेक गणमात्य लोगों की उपस्थिति में मनाया गया।

समारोह में विशिष्ट कार्य करने वाली 8 प्रतिभाओं को जोधपुर महाराजा ने सिरोपाव प्रदान कर सम्मानित किया। गज सिंह के एज्युकेटिव असिस्टेंट पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि जन्मदिन का मुख्य समारोह उम्मेद भवन पैलेस के राठौड़ दरबार हॉल में हुआ। गजसिंह परम्परागत राजसी पहनावे व हाथ में प्राचीन शाही तलवार व चेहरे पर अपनायत की मुस्कान के साथ राठौड़

दरबार हॉल में पहुंचे।

राजपुरोहितों व राज पंडितों ने की तिलक आरती

राजपुरोहितों व राजपण्डितों भगवान सिंह राजपुरोहित, राज व्यास सुरेश व्यास ,लहित त्रिवेदी, अश्विनी त्रिवेदी, अश्विनी देव व जितेंद्र जोशी द्वारा परम्परानुसार मंत्रोच्चारण के साथ तिलक आरती की व एज्युकेटिव असिस्टेंट पुष्पेन्द्रसिंह भाटी द्वारा मेवा-भिष्ठान थाल प्रस्तुत किया गया।

समारोह में सबसे पहले युवराज शिवराजसिंह ने पूर्व महाराजा गजसिंह को नजर निछरावल कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद राज भंवर

सिराजदेव ने दादोसा की नजर निछरावल की एवं जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

राठौड़ दरबार हाल में परंपरा के अनुसार पूर्व महाराज, पूर्व रावराजा, पूर्व सिरायत व पूर्व राजा, पूर्व ताजमी जागीरदार, मुस्सदी व विशिष्ट नागरिक, महाराजा के अतिथि, पूर्व जागीरदार, सरदार, नागरिक, मारवाड़ के राजपूत सरदार व पैलेस के पूर्व व वर्तमान अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नजर निछरावल कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

गजसिंह के मेहरानगढ़ से उम्मेद भवन पहुंचने पर मुख्य द्वार पर भंवर बाईजीलाल वारा राज्ने ने अगवानी कर कलश समारोह व आरती की। इस अवसर पर भंवर सिराजदेव भी दादोसा की अगवानी के लिए उपस्थित थे। उम्मेद

पैलेस के पोचें में पहुंचने पर मेहरानगढ़ बैड द्वारा धूंसा वादन किया।

जाना दरबार हॉल में गज सिंह को सबसे पहले बाईजीलाल शिवरंजनी राज्ये, भंवर बाईजी लाल वारा राज्ये, महारानी हेमलता राज्ये, युवरानी गायत्री राज्ये सहित अन्य पूर्व महाराज, पूर्व रावराजा, पूर्व जागीरदार परिवार कि महिलाओं द्वारा नजर निछरावल की गई।

गजसिंह ने राठौड़ दरबार हॉल के मुख्य समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 8 प्रतिभाओं को परम्परागत सिरोपाव प्रदान कर सम्मानित किया।

इनमें मेजर जनरल के वी एस लोलोजा को हाथी सिरोपाव, सुनील कला जीरम सिंह, पंडित सिंह , मुल सिंह सेवा को पालकी सिरिपाव व नाथू सिंह , आनंद सिंह व पूताराम को घोड़ा सिरोपाव प्रदान कर सम्मानित किया।

कार्यों की समीक्षा

पाली, (नि.सं.)। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी ली तथा एसडीआरएफ के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

उन्होंने पंच गौरव योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त बजट से किए जाने वाले कार्यों, व्यय, मशीनरी खरीद तथा राजीविका द्वारा महिलाओं को दी जा रही प्रशिक्षण गति.विधियों की निश्चिर्हित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने टाामीण सेवा शिविरों में प्राप्त चूई एवं पुरानी सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रगतिरत सड़कों, अटल प्रगति पथ एवं पूर्ण कार्य कर रहे आर.ए.ले हुए गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। जवाई जल मिशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित नल एवं विद्युत कनेक्शनों तथा पूर्ण किए गए कार्यों की जानकारी ली।

भटाना में विकास रथ का स्वागत

रेवदर, (निर्सं)।राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर सुशासन पखवाड़ा के तहत भटाना में आज विकास रथ का स्वागत किया। हमारा राजस्थान विकास रथ का भ्रमण कराया गया।

विकास रथ मकावल, भटाना होते हुए सोरडा गांवों में पहुंचा, जहां आमजन को राजस्थान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों तथा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। दीपेंद्र सिंह पीथापुरा, मंडल अध्यक्ष कुलदेव रामपुरा,युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह राव, मंडल महामंत्री गुलाम सिंह, दिनेश चौधरी, मोती राम, हरजी देवासी,हीरा लाल घासी, ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार नागर, रविन्द्र सिंह देवडा, पुलिस चौकी भटाना हेड कांस्टेबल गणेश राम,क्रमल गुर्जर कार्यवाहक प्रधानाचार्य,धर्मा राम,से सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

एम्बुलेंस दान कर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत कर रहा चोला एमएस

जोधपुर,(का.सं.)।राजस्थान,दिसंबर 2025: चोला मंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चोला एमएस) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत जोधपुर में इंडियन हेड इंजी फाउंडेशन (आईएचआईएफ) को एक रिहैबिलिटेशन कार्म बेसिक लाइफ सेविंग (बीप्लएफ) एम्बुलेंस दान की है। यह कदम समाज के कमजोर वगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करता है।

इस एम्बुलेंस का आधिकारिक लॉन्च आईएचआईएफ युवराज शिवराज सिंह न्यू रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, जोधपुर में किया गया। जरूरी लाइफ-सेविंग और रिहैबिलिटेशन उपकरणों से लैस यह एम्बुलेंस इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मरीज के

निगरानी समिति की बैठक हुई

जालोर,(नि.सं.)। जिले के लिए 17 संवहनीय विकास लक्ष्य-2030 के प्रभावी क्रियाव्यवन के लिए जिला स्तरीय एसडीजी क्रियाव्यवन एवं निगरानी समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्त की प्रतिबद्धता को दोहराया और राजस्थान एएसडीजी इंडेक्स-2025 में 14 लक्ष्यों के 100 इंडीकेटर्स पर जालोर जिले की स्थिति की समीक्षा कर संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जिला राज्य स्तरीय श्रेणीयन में अग्रणी जिलों में स्थान प्राप्त कर सके। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक डॉ. धनसिंह राजपुरोहित ने नवीनतम राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक, 2025 रिपोर्ट में जिले के एस्पिरेट व परफॉर्मर श्रेणी के संकेतकों की पीपीटी के माध्यम से विभागवार जानकारी दी। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकिशोर राठोरा, पीएचडी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा, मुख्य आयोजना अधिकारी महेश चावला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भेराराम जाणी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक कपिल लूणा, जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रामलाल जाट, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संगमराम देवासी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय रणकपुर-जवाई बांध महोत्सव शुरू

पाली,(नि.सं.)। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आगाज रविवार को हुआ। रविवार को जीप सफारी वन क्षेत्र रणकपुर में, पतंग उड़ाना और डीआईसी द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की गई। साथ ही हॉट एयर बैलूनिंग की भी आयोजन नगरपालिका सादई द्वारा होटल माना के निकट हैलीपैड ठाांड पर किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय रणकपुर जवाई बांध महोत्सव में पूरे दिन पर्यटकों ने हैलीपैड ठाांड पर हॉट एयर बैलून एवं पतंगबाजी का लुप्त उठाया। साथ ही फ़ूड स्टॉल्स पर पारंपरिक व्यंजनों के चटबोरे भी लिए।

शाम को रणकपुर मंदिर परिसर में दीपदान के साथ ही पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमग हो उठा। इस अवसर पर चूड़, नागौर, बालोतरा जसोल सहित अन्य जिलों के कलाकारों द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने

पीपा क्षत्रिय समाज के कलैंडर का विमोचन

जोधपुर, (कासं)। श्री पीपा क्षत्रिय राखेचा भाईपा समिति द्वारा प्रकाशित वर्ष 2026 के कलैण्डर का विमोचन भव्य समारोह में किया गया।

श्री पीपा क्षत्रिय राखेचा भाईपा समिति के तत्वावधान में प्रकाशित श्री पीपा क्षत्रिय समाज के 2026 के कलैण्डर का विमोचन कार्यक्रम इस बार श्री समस्त पीपा क्षत्रिय समाज, विधानगर भवन में रखा गया। दोपहर 1:15 बजे शुरू हुए इस समारोह में समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा संत पीपा जी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर माल्यार्पण किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीया जन्ता पार्टी जोधपुर शहर के महामंत्री ओमप्रकाश दहिया थे जबकि

श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा, मनोज मकवाणा, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी जोधपुर लालाराम भाटी, श्याम सुंदर दहिया, एडवोकेट प्रकाश पंवार, उद्यमी बाबूलाल मकवाना, समाजसेवी आशीष सोलंकी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राजस्थानी परंपरा के अनुसार सभी मंचासिन अतिथियों का साफा पहनाकर एवं दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा विज्ञापन दाताओं का दुपट्टा ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राखेचा भाईपा समिति के नारायण राखेचा, वसीलाम राखेचा, आसाराम राखेचा, टीकमचंद राखेचा, अनिल राखेचा, विशनाराम राखेचा,कैलाश

राखेचा, मनीष राखेचा, तुलसाराम राखेचा रामचंद्र राखेचा, प्रेम प्रकाश राखेचा, चेनाराम राखेचा,जसराम राखेचा सहित पूर्व अध्यक्ष आसुलाल दहिया पार्षद कब्बूलाल दहिया तथा श्री पीपा प्रकाश के संपादक नरेंद्र चौहान उपस्थित थे। पूर्व न्याति अध्यक्ष आसुलाल दहिया एवं मंचासिन अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ो महातुभावों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अतिथियों को राखेचा भाईपा के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम के अंत में राखेचा भाईपा समिति के अध्यक्ष जगदीश राखेचा ने आंगतुक सभी हुए समाज बंधुओ का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन सचिव तेजराम राखेचा ने किया।

शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों का सहयोग अतुलनीय : दक

जालोर,(का.सं.)। राज्य के सहकारिता एवं नागरिक उद्येयन मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों का सहयोग अतुलनीय है। जालोर जिले के दादाल प्राय में शान्ति देवी चतरमल जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 7 करोड़ की लागत से अधिक राशि से नवनिर्मित विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने अपने उद्बोधन में भामाशाह द्वारा विद्यालय भवन निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से जालोर जिले के बच्चे पढ़-लिखकर प्रशासनिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों

को स्किल डवलपमेंट के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के.विश्रनोई ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा सहित समाज कल्याण के हर क्षेत्र में भामाशाहों ने बढ़-चढ़कर सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रत्येक गांव-ढाणी तक ग्रामीणों को लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार के दो वर्ष के अल्पकालिक समय में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिसके फलस्वरूप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत को साकार करने में सहयोग मिला है। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि जोगेश्वर गांग ने कहा कि जालोर जिला भामाशाहों की भूमि है तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव अतुलनीय

रहा है। पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से जुड़कर भामाशाह परिवार को आभार जताते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह के दौरान भामाशाह परिवार द्वारा विद्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले स्व. मलसिंह परिवार का आभार जताया गया।समारोह से पूर्व अतिथियों द्वारा नवनिर्मित विद्यालय का फीता काट कर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. प्रदीप के. गांवडे, जसरज राजपुरोहित, दानाराम चौधरी, सायला उपखण्ड अधिकारी सूरजभान विश्रनोई, पुखराज विराणा, संजू सोलंकी, प्रकाश छाजेड, नैनमल लखारा सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, स्कूल छात्र-छात्राएं सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेसजनों ने प्रदर्शन किया

लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य का पालन करें : राणावत

पाली, (नि.सं.)। पाली पंचायत समिति सभागार मे सोमवार को मास्टर ट्रेनर द्वारा नव नियुक्त सुपरवाईजर एवं बी.एल.ओ को प्रशिक्षण देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि मिल मतदान केंद्रों पर नए बुथ बनाए गए हैं, उनके सुपरवाईजर एवं बी.एल.ओ को मास्टर ट्रेनर और प्रकाश कुमावत एवं जयपाल सिंह राठौड ने गहनता से प्रशिक्षण दिया। उन्हें फार्म नम्बर छह, सप्त, आठ, आठ क के अलावा अंडर टैकिंग फार्म भरने की प्रक्रिया के बारे मे जानकारी दी गई। राणावत ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी स्वच्छ व सही मतदाता सूची का निर्माण करते हुए लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य का पालन करें। अनिल नामा, रमेश अणकिया, सुरेश व्यास, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सैन, सवाई सिंह राजपुरोहित , लोकेश दवे, मनोज कुमार रॉणी, पारसराम, सुरेश चौधरी, अनिता पारीक आदि मौजूद रहे।

मांगी व भगवा आर में मिनी सचिवालय भवनों का लोकार्पण

बालोतरा, (निर्सं)। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को पंचायत समिति सिवाना की ग्राम पंचायत मांगी एवं भगवा आर में नवनिर्मित मिनी सचिवालय भवनों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने लोकार्पण उपरांत उपस्थित आमजन को संबोधित किया। विधायक भायल ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में लगातार कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

नवनिर्मित दोनों भवनों पर लाखों रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया गया है, जिससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि नवीन ग्राम पंचायतों के गठन से आमजन को प्रशासनिक सुविधाएं अब नजदीकी स्तर पर मिल रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में सिवाना विधानसभा क्षेत्र में 36 ग्राम पंचायतें एवं एक नवीन पंचायत समिति पादरू का गठन किया गया है, जिससे विकास कार्यों में और अधिक तेजी आएगी। इससे ग्रामीण जनता को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ कम दूरी पर

ही प्राप्त हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान विकास रथ के माध्यम से राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी भी जनता को दी गई।

विधायक भायल ने बताया कि ग्राम पंचायत मांगी एवं भगवा आर में स्थानीय विधायक विकास कोष से भी विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में महेश, चौधान, वीर सिंह सेला, मसरा राम देवासी, गौतम सिंह राजपुरोहित, जेदू सिंह, तुलसी देवी मेघवाल, प्रशासक मांगी एवं भगवा आर सहित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

समाधान के निर्देश दिए। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि जब-जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब-तब विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि भाखर71 बेस्ट में बरसाती जल संरक्षण को लेकर कई स्थानों पर एनीकट एवं बांधों का निर्माण हुआ है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला

है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भेजी गई डीपीआर का लाभ भी इसी क्षेत्र को मिलेगा। विधायक भायल ने कहा कि रमणिया, धीरा, पादरू सड़क को डबल करने को लेकर भी प्रयास किए जाएंगे। महेश बी. चौहान ने भी राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वीर सिंह सेला ने भी सभा को संबोधित किया।

भाजपा ने विकास को गति दी : भायल

बालोतरा, (निर्सं)। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित " ब?ता राजस्थान, हमारा राजस्थान विकास एलएंडी रथ का आज सिवाना पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेला, मांगी, धीरा, रमणिया, काडोडी, भागवा आर एवं भागवा वी में पहुंचने पर पूजा-अर्चना कर भव्य स्वागत किया गया।

विकास रथ के माध्यम से आमजन

को केंद्र व राजस्थान सरकार की विभिन्न जनहितैषी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

रमणिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकास रथ यात्रा सभा के साथ-साथ राज्य सरकार के फॉलोअप शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन विधायक हमीर सिंह भायल द्वारा किया गया। विधायक ने शिविर में विभागवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जनसमस्याओं के शीघ्र

समाधान के निर्देश दिए। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि जब-जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब-तब विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि भाखर71 बेस्ट में बरसाती जल संरक्षण को लेकर कई स्थानों पर एनीकट एवं बांधों का निर्माण हुआ है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला

मरीज जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं।

आईएचआईएफ ने बताया कि यह एम्बुलेंस बालेसर, ओसियां, तिनवारी, माथानिया और सलावास जैसे गांवों तक पहुंचेगी। इसके अलावा सूरसागर, बसनी, सांगरिया और नागौरी गेट जैसे शहर के उन क्षेत्रों तक भी जाएगी, जहाँ इलाज की सुविधाएँ कम हैं। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के साथ-साथ आईएचआईएफ लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा, ताकि न्यूरो-रिहैबिलिटेशन के बारे में जानकारी बढ़े और जरूरतमंदों को मुफ्त या कम लागत में इलाज मिल सके।

पहल यह स्पष्ट करती है कि चोला एमएस उन क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, जहाँ वह मौजूद है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक जमीनी स्तर पर और असरदार सहायता पहुंच सके।

नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े तीन करोड़ रुपए बदलने से हाईकोर्ट का इंकार

जोधपुर, (कासं)।नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े 3 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टेंबल जजमेंट में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये नोट अब रही हो गए हैं।

बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 16 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए मार्च 2017 में याचिका लगाई थी। इसके अलावा बाद में 6 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) ने भी अपने पुरानी करेंसी के करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए बदलने के लिए अलग-अलग याचिका लगा दी थी। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंधी की डिलीजन बेंच ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति सहित 7 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि आर्थिक नीतियों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। आरबीआई द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लगाई गई रोक जनहित में लिया गया सही फैसला था।

कोर्ट ने फैसले में लिखा कि महज कठिनाई या असुविधा, चाहे वह कितनी ही वास्तविक क्यों न हो। किसी बैंध आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उठाए गए नियामक उपायों को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकती।

बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने याचिका में बताया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के समय उनके पास 16 लाख 17 हजार 500 रुपए (500 और 1000 के नोट) की नकदी मौजूद थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ये पैसा किसानों और आम लोगों का है, जो बैंध तरीके से समिति के पास आया था लेकिन आरबीआई ने 14 और 17 नवंबर 2016 को सकूलर जारी कर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुराने नोट स्वीकार करने से रोक दिया। वकील ने कहा कि एक ही तरह की अन्य सोसायटियों ने नोट जमा करवा दिए, लेकिन याचिकाकर्ता को अनुमति न देना भेदभावपूर्ण है।

इस समिति के अलावा बामनोर, बिसरगिया, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट

न्यायाधीश गुप्ता नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे

भीनमाल, (निर्सं)। जुंजाणी रोड स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में जालोर जिला न्यायाधीश एवं भीनमाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को ऐतिहासिक शिवालय के दर्शन किए।

पुजारी तरुण त्रिवेदी ने जालोर जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता और भीनमाल के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महेंद्र कुमार टांक को विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। पूर्व जिला न्यायाधीश ने धारादल स्थित महालक्ष्मी कमलेश्वरी माताजी के दर्शन भी किए। मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता व भीनमाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महेंद्र कुमार टांक को सेवाविबुत्त रीडर बाबूसिंह राव ने नीलकंठ शिवालय की तस्वीर भेंट की। निवर्तमान पार्षद जयसिंह राव व साथी अधिवक्ताओं ने न्यायाधीशों का स्वागत किया। दर्शन करने आ आतिथियों ने नवनिर्मित मंदिर परिसर सुंदरता की प्रशंसा की। इस अवसर पर इस अवसर पर सेन. रीडर बाबूसिंह राव, निवर्तमान पार्षद जयसिंह, राव महासभा जिला संयोजक अशोकसिंह ओपावत, अधिवक्ता राजेंद्र नागर, अधिवक्ता प्रितमसिंह ईराणी, कपिल वैष्णव आदि मौजूद रहे।

</

